

20 June 2026: Top Current Affairs News GK (Hindi & English)

1] The India-Russia Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS), which came into operational light on June 20, 2026, primarily facilitates which operational mechanism between the two nations?

भारत-रूस पारस्परिक रसद विनिमय समझौता (RELOS), जो 20 जून 2026 को चर्चा में रहा, मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच किस परिचालन तंत्र को सुगम बनाता है?

A. Joint Space Exploration and Satellite Launching / संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण

B. Reciprocal Logistics, Refueling, and Berthing Facilities for Military Assets / सैन्य संपत्तियों के लिए पारस्परिक रसद, ईंधन भरने और बर्थिंग की सुविधा (Reciprocal Logistics for Military Assets)

C. Trilateral Energy Pipeline Corridor via Central Asia / मध्य एशिया के माध्यम से त्रिपक्षीय ऊर्जा पाइपलाइन कॉरिडोर

D. Direct Bilateral Agricultural Trade Clearance / प्रत्यक्ष द्विपक्षीय कृषि व्यापार निकासी

✓ **Answer: B. Reciprocal Logistics, Refueling, and Berthing Facilities for Military Assets** / सैन्य संपत्तियों के लिए पारस्परिक रसद, ईंधन भरने और बर्थिंग की सुविधा

Explanation: The Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS) between India and Russia allows the military assets (navy ships and aircraft) of both nations to access logistics, refueling, and maintenance facilities at each other's bases. On June 20, 2026, Indian authorities dismissed misleading social media speculation about foreign troop stationing, clarifying that RELOS is strictly a routine administrative and logistics-sharing framework to enhance maritime security, not a formal military defense alliance.

स्पष्टीकरण: भारत और रूस के बीच 'पारस्परिक रसद विनिमय समझौता' (RELOS) दोनों देशों की सेनाओं (नौसेना के जहाजों और विमानों) को एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर रसद, ईंधन भरने और रखरखाव सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। 20 जून 2026 को,

भारतीय अधिकारियों ने विदेशी सैनिकों की तैनाती से जुड़ी सोशल मीडिया की भ्रामक अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि RELOS केवल एक प्रशासनिक और रसद साझाकरण ढांचा है, न कि कोई सैन्य गठबंधन।

2] In the newly released World Economic Forum's (WEF) Energy Transition Index (ETI 2026), what rank has India secured globally?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी 'एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स' (ETI 2026) में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है?

- A. 65th / 65वां
- B. 70th / 70वां (70th Spot)
- C. 75th / 75वां
- D. 82nd / 82वां

Answer: B. 70th / 70वां (70th Spot)

Explanation: According to the World Economic Forum's (WEF) annual "Energy Transition Index (ETI 2026): Insight Report" released in June 2026, India jumped 2 places to secure the 70th spot globally with an overall score of 54.9. The index, which tracks nations on clean energy readiness, equity, and sustainability, was topped by Sweden (1st), followed by Finland (2nd) and Denmark (3rd).

स्पष्टीकरण: जून 2026 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी वार्षिक "एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI 2026)" रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2 स्थानों की छलांग लगाकर 54.9 के समग्र स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 70वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वच्छ ऊर्जा तत्परता, समानता और स्थिरता के आधार पर देशों को रैंक करने वाले इस सूचकांक में स्वीडन पहले, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा।

3] The Union Cabinet recently approved a massive climate mitigation infrastructure outlay. What is the total budget approved for India's new nationwide Industrial Carbon Capture and Storage Scheme?

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जलवायु शमन बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़े बजट को मंजूरी दी है। भारत की नई देशव्यापी 'औद्योगिक कार्बन कैप्चर और स्टोरेज योजना' के लिए कितनी कुल राशि स्वीकृत की गई है?

- A. ₹12,500 crore / ₹12,500 करोड़

- B. ₹15,000 crore / ₹15,000 करोड़
- C. ₹19,700 crore / ₹19,700 करोड़ (₹19,700-crore)
- D. ₹25,000 crore / ₹25,000 करोड़

✓ **Answer: C. ₹19,700 crore / ₹19,700 करोड़ (₹19,700-crore)**

Explanation: To help India accelerate towards its net-zero climate goals, the Union Cabinet officially approved a landmark ₹19,700-crore Carbon Capture and Storage (CCS) scheme. The funding will be deployed to establish high-tech carbon capture facilities across carbon-heavy industrial sectors, including steel plants, cement manufacturing, and thermal power units, to directly prevent emissions from entering the atmosphere.

स्पष्टीकरण: भारत को अपने नेट-जीरो (शुद्ध-शून्य) जलवायु लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए, केंद्रीय कैबिनेट ने ₹19,700 करोड़ की ऐतिहासिक कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) योजना को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग स्टील प्लांट, सीमेंट निर्माण और थर्मल पावर जैसी भारी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में जाने से पहले रोकने के लिए किया जाएगा।

4) In a historic judgment delivered around June 20, 2026, the Supreme Court of India declared walking on a demarcated footpath as which type of right for citizens?

20 जून 2026 के आसपास दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीमांकित फुटपाथ (footpath) पर चलने को नागरिकों के लिए किस प्रकार का अधिकार घोषित किया है?

- A. Statutory Right / वैधानिक अधिकार
- B. Fundamental Right / मौलिक अधिकार (Fundamental Right)
- C. Directive Principle / राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत
- D. Customary Civil Right / प्रथागत नागरिक अधिकार

✓ **Answer: B. Fundamental Right / मौलिक अधिकार (Fundamental Right)**

Explanation: In a landmark ruling aimed at restructuring urban infrastructure and safeguarding pedestrian safety, the Supreme Court of India declared that walking on a demarcated, unobstructed footpath is a Fundamental Right under

Article 21 (Right to Life). The apex court ordered local administrative bodies to clear illegal encroachments and ensure safe walkable spaces in all major metropolitan areas.

स्पष्टीकरण: शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि एक साफ और बाधा रहित फुटपाथ पर चलना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक 'मौलिक अधिकार' है। शीर्ष अदालत ने स्थानीय प्रशासनिक निकायों को सभी प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने और सुरक्षित पैदल चलने योग्य स्थान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

5) **India's first mega commercial plant designed to produce Ammonium Nitrate directly from coal gasification is being set up in which state with an investment of ₹25,000 crore?**

₹25,000 करोड़ के निवेश के साथ कोयला गैसीकरण (coal gasification) के माध्यम से सीधे अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने वाला भारत का पहला मेगा वाणिज्यिक संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है?

- A. Jharkhand / झारखंड
- B. Odisha / ओडिशा (Odisha)
- C. Chhattisgarh / छत्तीसगढ़
- D. Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश

✓ **Answer: B. Odisha / ओडिशा (Odisha)**

Explanation: The Prime Minister laid the foundation stone for India's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate project in Odisha, backed by an investment of ₹25,000 crore. Utilizing domestic coal gasification technology, the facility will produce ammonium nitrate—a critical raw material for fertilizers and industrial explosives—thereby reducing India's heavy import dependence.

स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री ने ओडिशा में ₹25,000 करोड़ के निवेश से बनने वाले भारत के पहले वाणिज्यिक-स्तरीय 'कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट' (coal-to-ammonium nitrate) प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। घरेलू कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके, यह संयंत्र अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगा—जो उर्वरकों और औद्योगिक विस्फोटकों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है—जिससे भारत की आयात निर्भरता कम होगी।

6] Who has become the first Indian official to be appointed as the Vice President of the Financial Action Task Force (FATF) in June 2026?

जून 2026 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के उपाध्यक्ष (Vice President) के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं?

- A. T. Raja Kumar / टी. राजा कुमार
- B. Vivek Aggarwal / विवेक अग्रवाल (Vivek Aggarwal)
- C. Sanjay Kumar Mishra / संजय कुमार मिश्रा
- D. Urjit Patel / उर्जित पटेल

Answer: B. Vivek Aggarwal / विवेक अग्रवाल (Vivek Aggarwal)

Explanation: Marking a massive diplomatic boost for India's standing in global financial governance, senior Indian official Vivek Aggarwal has been appointed as the Vice President of the Financial Action Task Force (FATF). This is the first time an Indian representative has secured this apex leadership position in the global money laundering and terrorist financing watchdog.

स्पष्टीकरण: वैश्विक वित्तीय शासन में भारत की स्थिति को बड़ा राजनयिक प्रोत्साहन देते हुए, वरिष्ठ भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रतिनिधि ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की निगरानी करने वाली इस वैश्विक संस्था में यह शीर्ष नेतृत्व पद हासिल किया है।

7] The 16th BRICS Agriculture Ministers' Meeting concluded with the unanimous adoption of the 'Indore Declaration'. Which nation currently holds the BRICS Presidency facilitating this meeting?

16वीं ब्रिक्स (BRICS) कृषि मंत्रियों की बैठक 'इंदौर घोषणापत्र' (Indore Declaration) को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ समाप्त हुई। इस बैठक की मेजबानी करने वाली ब्रिक्स की अध्यक्षता वर्तमान में किस देश के पास है?

- A. Brazil / ब्राजील
- B. Russia / रूस
- C. India / भारत (India's BRICS Presidency)

D. South Africa / दक्षिण अफ्रीका

✓ **Answer: C. India / भारत (India's BRICS Presidency)**

Explanation: Under India's BRICS Presidency, the 16th BRICS Agriculture Ministers' Meeting was held in Indore, Madhya Pradesh. The meeting concluded with the signing of the 'Indore Declaration,' under which member countries agreed to cooperate on building resilient agricultural chains, tech innovations, and mitigating global food security risks.

स्पष्टीकरण: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, मध्य प्रदेश के इंदौर में 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 'इंदौर घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई, जिसके तहत सदस्य देश लचीली कृषि श्रृंखलाओं, तकनीकी नवाचारों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा जोखिमों को कम करने पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए।

8 **Union Minister Pralhad Joshi on June 19-20, 2026, inaugurated advanced quality testing laboratories at the National Test House (NTH). Which unique specialty testing facility was unveiled at NTH Northern Region in Ghaziabad?**

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 19-20 जून 2026 को नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) में उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में NTH उत्तरी क्षेत्र में किस अनूठी विशेषता वाली परीक्षण सुविधा का अनावरण किया गया?

- A. Microbiological Testing Laboratory / माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण प्रयोगशाला
- B. Shoe Testing Facility / जूता परीक्षण सुविधा (Shoe Testing Facility)
- C. Semiconductor Wafer Testing Center / सेमीकंडक्टर वेफर परीक्षण केंद्र
- D. EV Battery Diagnostic Lab / ईवी बैटरी डायग्नोस्टिक लैब

✓ **Answer: B. Shoe Testing Facility / जूता परीक्षण सुविधा (Shoe Testing Facility)**

Explanation: Union Minister Pralhad Joshi inaugurated multiple state-of-the-art laboratory facilities for the National Test House (NTH). While a modern Microbiological Testing Laboratory was established in Mumbai (Western Region), a dedicated, high-tech Shoe Testing Facility was unveiled in Ghaziabad (Northern Region) to strengthen quality standards and export compliance for the domestic footwear industry.

स्पष्टीकरण: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) के लिए कई अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं का उद्घाटन किया। जहां मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र) में एक आधुनिक माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई, वहीं घरेलू फुटवियर उद्योग के लिए गुणवत्ता मानकों और निर्यात अनुपालन को मजबूत करने के लिए गाजियाबाद (उत्तरी क्षेत्र) में एक समर्पित 'जूता परीक्षण सुविधा' (Shoe Testing Facility) का अनावरण किया गया।

9) **The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) under the Ministry of Home Affairs launched two new portals in June 2026. What is the specific name of the operational module launched to assist victims in tracing and reclaiming defrauded money?**

गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने जून 2026 में दो नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। पीड़ितों को धोखाधड़ी से उड़ाए गए पैसे को वापस पाने (reclaim) में मदद करने के लिए लॉन्च किए गए मॉड्यूल का विशिष्ट नाम क्या है?

- A. Cyber Suraksha Portal / साइबर सुरक्षा पोर्टल
- B. Money Restoration Module (MRM) / मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM)
- C. Digital Dhan Fraud Check / डिजिटल धन फ्रॉड चेक
- D. Financial Victims Escalation Matrix / फाइनेंशियल विक्टिम्स एस्केलेशन मैट्रिक्स

Answer: B. Money Restoration Module (MRM) / मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM)

Explanation: To check growing financial cyber frauds, the MHA's Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) deployed two digital channels: the Grievance Redressal Mechanism (GRM) and the Money Restoration Module (MRM). The MRM is custom-engineered to synchronize operational communication between affected banks, payment gateways, and police units to freeze stolen amounts instantly and automate restoration to the victim's account.

स्पष्टीकरण: बढ़ते वित्तीय साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए, गृह मंत्रालय के I4C ने दो डिजिटल चैनल शुरू किए हैं: शिकायत निवारण तंत्र (GRM) और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM)। MRM को विशेष रूप से प्रभावित बैंकों, पेमेंट गेटवे और पुलिस इकाइयों के बीच संचार को तेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि चोरी की गई राशि को तुरंत फ्रीज (freeze) किया जा सके और पीड़ित के खाते में उसकी वापसी स्वचालित की जा सके।

10 The Reserve Bank of India (RBI) on June 19-20, 2026, updated structural regulations under the Kisan Credit Card (KCC) scheme. What primary modification was enforced through this notification?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19-20 जून 2026 को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत संरचनात्मक नियमों को अपडेट किया है। इस अधिसूचना के माध्यम से कौन सा प्राथमिक संशोधन लागू किया गया है?

- A. Complete removal of credit limits / क्रेडिट सीमा को पूरी तरह हटाना
- B. Standardization of Crop Season Definitions via tech-integration / तकनीकी-एकीकरण के माध्यम से फसल सीजन की परिभाषाओं का मानकीकरण (Standardising crop season definitions)
- C. Compulsory inclusion of urban livestock / शहरी पशुधन का अनिवार्य समावेश
- D. Transitioning entirely to cryptocurrency payouts / पूरी तरह से क्रिप्टोकॉर्सेसी भुगतान में संक्रमण

✓ **Answer: B. Standardization of Crop Season Definitions via tech-integration** / तकनीकी-एकीकरण के माध्यम से फसल सीजन की परिभाषाओं का मानकीकरण

Explanation: To eliminate administrative ambiguities and ensure frictionless crop insurance claims, the RBI revised and standardized the definitions of crop seasons under the Kisan Credit Card (KCC) scheme across Indian states. Powered by digital satellite profiling, this standardization allows financial institutions to disburse credit and evaluate repayment cycles accurately aligned with localized harvesting cycles.

स्पष्टीकरण: प्रशासनिक विसंगतियों को दूर करने और फसल बीमा दावों को सुगम बनाने के लिए, आरबीआई (RBI) ने भारतीय राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत फसल सीजनों की परिभाषाओं को संशोधित और मानकीकृत किया है। डिजिटल सैटेलाइट प्रोफाइलिंग द्वारा संचालित यह मानकीकरण वित्तीय संस्थानों को स्थानीय कटाई चक्रों के अनुसार सटीक रूप से ऋण वितरित करने और पुनर्भुगतान चक्र का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।